

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, बृहस्पति वार, जुलाई 23, 1970/श्रावण 1, 1892

No. 15] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 1970/SRAVANA 1, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF DEFENCE

(Navy Branch)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June 1970

**S.R.O. 21-E.**—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Services and Miscellaneous Regulations, 1964, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 22E, dated the 19th February, 1964, namely:—

1. These regulations may be called the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Eighth Amendment) Regulations, 1970.

2. In the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1964—

(i) in regulations 122 and 128, after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(6-A) Declaration—Before a candidate reports for training, he and his parent or guardian are required to sign a bond, as given in Appendix XI.”

(ii) after regulation 166, the following regulation shall be inserted, namely:—

“166-A Declaration—Before a candidate reports for training he and his parent or guardian are required to sign a bond, as given in Appendix XI.”

## APPENDIX XI

## DECLARATION

**BOND TO BE SIGNED BY PARENT/GUARDIAN AND THE CANDIDATE  
SELECTED FOR INITIAL TRAINING WITH A VIEW TO BEING COMMISSIONED IN THE REGULAR NAVY**

1. This agreement dated ..... date of ..... between ..... son of ..... resident of ..... (hereinafter called 'the Guarantor' which expression shall include his personal representative when the context so admits) of the first part and ..... son/ward of the aforesaid Guarantor (hereinafter called 'the Officer') of the second part and the President of India (hereinafter called "the Government" which expression shall include a successor and assigns where the context so admits) of the third part.

2. Whereas the Officer has been selected by the Government on the terms hereafter appearing for the purpose of receiving initial training with a view to being Commissioned as an officer in the Regular Navy, provided he is considered by the Government to be suitable in all respects.

3. Now it is agreed between the parties referred to above that in consideration of the Officer being selected by the Government for the purpose of the aforesaid training, the guarantor covenants with the Government that the officer will attend the aforesaid training, as the Government may determine from time to time for the prescribed periods or until he is declared fit (as to which the decision of the appropriate authority prescribed by the Government for the time being shall be final) to hold the assigned appointment and also complete the prescribed period of probationary period, unless he, the Officer is prevented from doing so by death or on account of ill health or some other reason over which the officer has no control or by being removed on the ground that the Officer is considered by the said appropriate authority to be unfit to continue as an officer on probation.

4. If for any reason not beyond the control of the officer, he does not complete the prescribed period of his training and probation or does not hold appointment assigned to him then the guarantor and the officer shall jointly and severally, be liable to pay forthwith to the Government in cash such sum as the Government shall fix, but not exceeding such expenses as shall have been incurred by the Government on account of the officer on his training and all monies received by the officer as pay and allowances from the Government together with interest on the said monies calculated at the rate in force for Government loans.

5. The guarantor further agrees that the guarantor shall not be relieved from his liability by reason of any variation of the terms or of any indulgence by the Government to the officer or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have effect of so relieving the guarantor.

6. And it is lastly agreed that if there is any dispute as to the effect or meaning of these presents, the decision of which has not been expressly hereinbefore provided for, the same shall be referred to the decision of the Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence, whose decision shall be final. In witness whereof the parties have thereto set their respective hands the day and year first before written.

Signed by the Guarantor  
in the presence of

Signed by the said officer  
in the presence of

Signed on behalf of the  
President of India in the  
presence of.

V. SUBRAHMANYAN, Jt. Secy.

## रक्षा मंत्रालय

## (नौसेना शाखा)

## अधिसूच 1

नई दिल्ली, 6 जून, 1970

का० नि० आ० 21-E.—नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 22-इ, तारीख 19 फरवरी, 1964 के साथ प्रकाशित नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण, विनियम, 1964 में, और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. ये विनियम नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (आठवीं संशोधन) विनियम, 1969 कहे जा सकेंगे :

2 नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1964 में:—

(i) विनियम 122 और 128 में, उपविनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(6-क) घोषणा—इससे पूर्व कि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए आए, उससे और उसके माता पिता या अभिरक्षक से यह अपेक्षित है कि वे उपाबंध XI में दिए हुए बन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर करें।”

(ii) विनियम 166 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“166-क-घोषणा—इससे पूर्व कि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए आए, उससे और उसके माता-पिता या संरक्षक से यह अपेक्षित है कि वे उपाबंध XI में दिए हुए बन्धपत्र पर हस्ताक्षर करें।”

## उपाबन्ध

## घोषणा

नियमित नौसेना में आयुक्त कर लिये जाने कि दृष्टि से आरम्भिक प्रशिक्षण के लिए खयम लिए गए अभ्यर्थी और उसके माता-पिता/संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला बन्ध-पत्र

प्रथम पक्षकार श्री..... पुत्र श्री..... निवासी..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्याभूतिदाता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत, जब प्रसंग से ऐसा अपेक्षित हो, उसका वैयक्तिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा) द्वितीय पक्षकार, उपर्युक्त प्रत्याभूति का पुत्र/प्रतिपात्य श्री..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘आफीसर’ कहा गया है); तृतीय पक्षकार, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्, ‘सरकार’ कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब प्रसंग से ऐसा अपेक्षित हो, उनका पदोत्तरवर्ती और समनुदेशी भी सम्मिलित होगा) के बीच..... के..... दिन किया गया यह करार।

2. यतः आफिसर का चयन सरकार ने एतद्व्यवस्थात् दिए गए निबन्धनों पर इस दृष्टि से कि उसे नियमित नौसेना में आफिसर के रूप में आयुक्त कर लिया जाए, परन्तु यह तब जब कि सरकार उसे सभी दफ्तर में उपयुक्त समझे, प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाने के प्रयोजन के लिए किया है।

3. अब ऊपर निर्दिष्ट पक्षकारों के बीच यह करार हुआ है कि उपर्युक्त प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा आफिसर का चयन कर लिए जाने के प्रतिफलस्वरूप, प्रत्याभूतिदाता सरकार के साथ यह प्रसविदा करता है कि वह आफिसर उपर्युक्त प्रशिक्षण में, जैसा सरकार समय समय पर अवधारित करे, विहित कालावधियों के लिए या तब तक जब तक कि वह योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता (जिनकी बाबत सरकार द्वारा तत्समय विहित समुचित प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा), हाजिर रहेगा, समनुदेशित नियुक्ति धारित करेगा और परिवीक्षा कालावधि की विहित कालावधि भी पूरी करेगा उस वशा को छोड़ कर जबकि आफिसर मृत्यु के कारण या खराब स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य ऐसे कारण से जिस पर उस आफिसर का कोई नियंत्रण न हो, अथवा इस आधार पर हटा दिए जाने से कि उक्त समुचित प्राधिकारी द्वारा वह आफिसर परिवीक्षा पर आफिसर के रूप में बने रहने के अयोग्य है, ऐसा करने से निवारित हो।

4. यदि किसी ऐसे कारण से जो आफिसर के नियंत्रण के परे न हो, वह अपने प्रशिक्षण की और परिवीक्षा की विहित कालावधि पूरी नहीं करता है या अपने को समनुदेशित नियुक्ति धारित नहीं करता है तो प्रत्याभूतिदाता और वह आफिसर, संयुक्ततः और पृथक्तः, सरकार को तत्काल ऐसी नकद राशि संदत्त करने के दायित्वाधीन होंगे जो सरकार नियत करेगी किन्तु वह राशि उन व्ययों से जो सरकार द्वारा उस आफिसर लेखे उसके प्रशिक्षण पर उपगत किए गए हों और उसके साथ उस आफिसर द्वारा सरकार से वेतन और भत्तों के रूप में प्राप्त सभी धन और उक्त धनों पर सरकारी उधारों के लिए प्रवृत्त दर पर संगणित व्याज, से अधिक नहीं होगी।

5. प्रत्याभूतिदाता यह भी करार करता है कि प्रत्याभूतिदाता निबन्धनों में किसी फेरबदल के या सरकार द्वारा उस आफिसर के प्रति किसी अनुग्रह के कारण अथवा किसी ऐसी बात या चीज के कारण, चाहे वह कुछ भी हो, जिसका प्रभाव प्रतिभूतिदाता से संबद्ध विधि के अधीन, इस उपबंध के न होने पर, प्रत्याभूतिदाता को इस प्रकार भुगत करना होता, अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

6. और अंत में यह करार पाया जाता है कि इन क्लिष्टों के प्रभाव या अर्थ के बारे में यदि कोई विवाद हुआ, जिसके विनिश्चय की बाबत इनमें इसके पूर्व कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है, तो वह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सचिव को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा। इसके साक्षीस्वरूप पक्षकारों ने पहले लिखे दिन और वर्ष को इस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

प्रत्याभूतिदाता द्वारा  
निम्नलिखित की उपस्थिति  
में हस्ताक्षरित

उक्त आफिसर द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, निम्नलिखित  
की उपस्थिति में हस्ताक्षरित . . . . .

बी० सुबराह्मामिन, संयुक्त सचिव।